RNI No#MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 13 जून से 19 जून 2026 भोपाल , मध्यप्रदेश से प्रकाशित वर्ष- 13 अंक-96 पृष्ठ- 8 मूल्य- रु. 5 /-

विश्व बैंक ने वैश्विक विकास दर घटाई: भारत 6.6% की दर से बढ़ेगा, ईरान तनाव के बावजूद मजबूत

वैश्विक सुस्ती से सतर्कता बरतें, लेकिन भारत की घरेलू ग्रोथ स्टोरी बनी हुई आकर्षक

नई दिल्ली: विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक विकास दर का अनुमान घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया है। एजेंसी ने अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष को इस कटौती का प्रमुख कारण बताया है। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं।

दूसरी ओर, विश्व बैंक ने भारत की विकास दर का अनुमान 6.6 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। भारत की मजबूत घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र की वृद्धि और सरकारी नीतियों को इस सकारात्मक अनुमान का आधार बताया गया है। हालांकि, बढ़ती तेल कीमतों से महंगाई और चालू खाता घाटे पर दबाव पड़ सकता है।

यह रिपोर्ट वैश्विक बाजारों के लिए सतर्क संकेत है। ईरान संघर्ष से तेल की कीमतों और मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा है, जिससे वैश्विक इक्विटी बाजार प्रभावित हो सकते हैं।

भारत के लिए स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन निवेशकों को तेल कीमतों और मुद्रास्फीति पर नजर रखनी चाहिए। ऑटो, एयरलाइंस और तेल आयात पर निर्भर कंपनियों पर दबाव पड़ सकता है। वहीं, घरेलू खपत, इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय सेवाओं से जुड़े सेक्टर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

निवेशक पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन बनाए रखें और डिफेंसिव थीम पर फोकस करें। RBI की मौद्रिक नीति और वैश्विक तेल कीमतों की गतिविधियां आगे के रुख को निर्धारित करेंगी। लंबी अवधि के निवेशक भारत की संरचनात्मक विकास कहानी पर भरोसा बनाए रख सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के नेतृत्व में रोजगार अभियान को सराहा: मध्य प्रदेश में नई नौकरियों की लहर

औद्योगिक विकास और कौशल विकास से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती, नए निवेश के अवसर

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे रोजगार अभियान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना, कौशल विकास मिशन और औद्योगिक निवेश के जरिए युवाओं को नई दिशा मिल रही है।

राज्य में सीमेंट, ऑटोमोबाइल, पावर, सोलर और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बड़े निवेश हो रहे हैं, जिससे हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हो रहे हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं के लिए नए अवसर खुल रहे हैं। सरकार कौशल विकास पर जोर दे रही है ताकि युवा उद्योगों की जरूरत के अनुसार तैयार हो सकें।

यह रोजगार अभियान मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास यात्रा के लिए सकारात्मक संकेत है। बढ़ते रोजगार और कौशल विकास से राज्य में निवेश का माहौल और बेहतर होगा। लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियों को स्थानीय स्तर पर कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध होने से फायदा होगा।

निवेशक मध्य प्रदेश में नए प्रोजेक्ट्स, औद्योगिक नीतियों और रोजगार सृजन के आंकड़ों पर नजर रखें। राज्य सरकार की सक्रियता और केंद्र की योजनाओं का समन्वय लंबी अवधि में स्थिर और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करेगा।

Credit Guarantee Scheme for MFIs Extended: Fresh Boost to Microfinance and Financial Inclusion

Extended Scheme to Support Credit Flow to Underserved Segments and Strengthen MFI Sector Growth

New Delhi: The government has extended the Credit Guarantee Scheme for Micro Finance Institutions (MFI 2.0), providing continued risk coverage for loans extended by MFIs to micro-enterprises and low-income borrowers. The extension will ensure uninterrupted credit support to the microfinance sector, which plays a vital role in financial inclusion and grassroots economic development.

Under the scheme, MFIs receive credit guarantees that help them access funds from banks and financial institutions at lower costs. This reduces the risk of lending to vulnerable segments, including women entrepreneurs and small borrowers in rural and semi-urban areas.

The extension is expected to sustain the momentum of micro-enterprise growth and support job creation at the bottom of the pyramid.

The extension is a positive development for the microfinance sector. Listed entities such as Bandhan Bank, Ujjivan Small Finance Bank, and other MFI-focused players stand to benefit from improved liquidity and risk mitigation. The scheme also indirectly supports fintech companies and NBFCs engaged in inclusive lending.

Long-term investors can consider selective exposure to the microfinance and financial inclusion theme.

While asset quality remains a key monitorable, the extended government backing provides stability and growth visibility. Investors should track disbursement trends, portfolio quality, and regulatory developments in the microfinance space for better-informed decisions.

रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 449 करोड़ का GNSS जैमर अनुबंध किया: नौसैनिक सुरक्षा को मिलेगा नया बल

रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्टॉक्स में नई संभावनाएं

नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 20 उन्नत क्षमता वाले ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सौदा नौसेना की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

ये उन्नत जैमर दुश्मन द्वारा GNSS सिग्नल को जाम या स्पूफ करने की कोशिशों से नौसेना के जहाजों और विमानों की सुरक्षा करेंगे। इससे हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक अभियानों की विश्वसनीयता बढ़ेगी। यह अनुबंध स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने वाली नीति के अनुरूप है।

यह सौदा रक्षा क्षेत्र, खासकर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए सकारात्मक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ा रहा है, जिससे BEL, L&T, HAL और अन्य निजी डिफेंस कंपनियों को नए ऑर्डर मिलने की संभावना है।

लंबी अवधि के निवेशक रक्षा क्षेत्र की कंपनियों पर ध्यान दे सकते हैं। सरकार के बढ़ते रक्षा बजट और स्वदेशीकरण फोकस से यह सेक्टर अगले कुछ वर्षों में मजबूत ग्रोथ दिखा सकता है। निवेशक अनुबंध की प्रगति और भविष्य के और ऑर्डर पर नजर रखें। यह कदम भारत की सामरिक क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ रक्षा उद्योग में निवेश के नए अवसर पैदा करेगा।

फिच ने भारत की विकास दर घटाई: अमेरिका-ईरान तनाव से अर्थव्यवस्था पर छाया संकट

महंगाई 5.3% तक पहुंचने का खतरा, बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है

नई दिल्ली: फिच रेटिंग्स ने भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया है। एजेंसी ने अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव को इस कटौती का मुख्य कारण बताया है। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं।

फिच का कहना है कि इस भू-राजनीतिक अस्थिरता से भारत की आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। महंगाई दर 5.3 प्रतिशत तक पहुंचने का खतरा भी जताया गया है। इससे उपभोक्ता खर्च पर दबाव बढ़ेगा और रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर भी असर पड़ सकता है।

यह रिपोर्ट शेयर बाजार के लिए सतर्क संकेत है। इक्विटी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है, खासकर ऑटो, एयरलाइंस और तेल आयात पर निर्भर कंपनियों पर दबाव पड़ सकता है।

निवेशक डिफेंसिव सेक्टर जैसे FMCG, फार्मा और यूटिलिटी पर फोकस कर सकते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में भी सतर्कता बरतनी चाहिए। लंबी अवधि के निवेशक वैश्विक घटनाओं पर नजर रखें और पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन बनाएं रखें। RBI की अगली नीति बैठक महत्वपूर्ण होगी।

एथेनॉल ब्लेंडिंग पर एक्साइज ड्यूटी जीरो: तेल आयात घटाने की बड़ी पहल, किसान समृद्धि और हरित ऊर्जा को मिलेगा बल

इथेनॉल उत्पादन, चीनी उद्योग और ऑटो सेक्टर में नई ग्रोथ संभावनाएं, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती

भोपाल: केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को शून्य कर दिया है। 22 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक इथेनॉल ब्लेंडिंग पर टैक्स माफी दी गई है। यह कदम देश के कच्चे तेल आयात को काफी कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

वर्तमान में भारत अपना अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा का भारी खर्च होता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने से न केवल आयात बिल घटेगा, बल्कि घरेलू इथेनॉल उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है, जिससे किसानों की आय में सीधा इजाफा होगा। सरकार का लक्ष्य इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20 प्रतिशत से आगे बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक ले जाना है।

इस नीति से चीनी मिलों और इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को नया बाजार मिलेगा। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण कम होगा क्योंकि इथेनॉल मिश्रित ईंधन से वाहनों से निकलने वाले कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के बढ़ते चलन के साथ यह नीति और प्रभावी साबित होगी।

यह घोषणा इथेनॉल उत्पादन, चीनी उद्योग और हरित ऊर्जा सेक्टर के लिए बहुत सकारात्मक है। लिस्टेड शुगर कंपनियां, इथेनॉल उत्पादक इकाइयां और संबंधित सप्लाई चेन को लंबी अवधि में फायदा होने की उम्मीद है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में फ्लेक्स-फ्यूल वाहन बनाने वाली कंपनियों को भी नए अवसर मिलेंगे। निवेशक इथेनॉल पॉलिसी की प्रगति, ब्लेंडिंग टारगेट की प्राप्ति और कृषि उपज की कीमतों पर नजर रखें। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर और वाहन अनुकूलन जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन सरकार का यह कदम ऊर्जा आत्मनिर्भरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है। लंबी अवधि के निवेशक हरित ऊर्जा और एग्री-बेस्ड इंडस्ट्री थीम पर ध्यान दे सकते हैं।

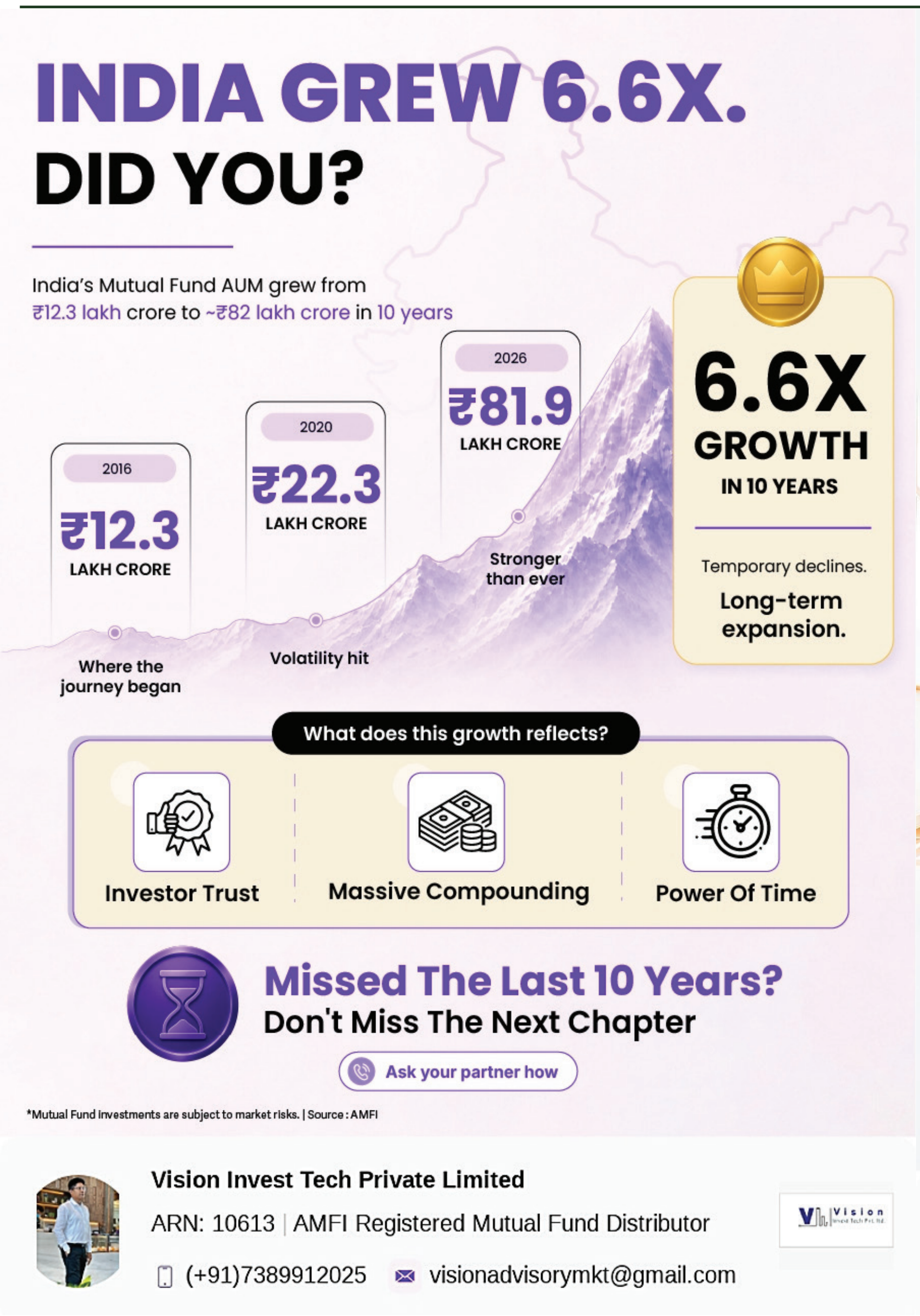

Reliance and Meta to Build India's First AI Data Center in Jamnagar: Strategic Leap Toward Digital Sovereignty

Investment Opportunity in AI Infrastructure: Massive Partnership to Accelerate Reliance's Tech Ambitions and Position India as a Global AI Hub

Mumbai: In a landmark development for India's technology landscape, Reliance Industries and Meta have announced plans to build the country's first large-scale AI data center in Jamnagar, Gujarat. The project marks a significant step in strengthening India's digital infrastructure and reducing dependence on foreign data centers.

The proposed facility will be equipped with advanced AI and high-performance computing capabilities, enabling faster processing of large datasets for machine learning, generative AI, and cloud services. Jamnagar's selection is strategic, leveraging Reliance's existing world-class refinery and petrochemical complex, along with its ambitious green energy and renewable power projects. This integration will help meet the massive energy and cooling requirements of an AI data center while supporting sustainability goals.

The data center is expected to play a critical role in supporting India's growing digital economy, including e-commerce, fintech, healthcare analytics, and government digital initiatives. It will also provide a secure, localized environment for data processing, aligning with the government's push for data sovereignty under the IndiaAI Mission.

This collaboration is highly positive for Reliance Industries, reinforcing its transformation from a traditional energy and petrochemical giant into a diversified technology and digital infrastructure player. The project is likely to boost investor confidence in RIL's long-term tech strategy and open new revenue streams in cloud and AI services.

The development also creates ripple effects across the broader ecosystem. Companies involved in semiconductors, power transmission, cooling technology, and data center construction stand to benefit indirectly. Long-term investors can view this as a strong signal for the AI and digital infrastructure theme in India.

While execution timelines, regulatory approvals, and capital expenditure will be key monitorables, the strategic importance of the project cannot be overstated. It positions India more competitively in the global AI race and offers investors exposure to one of the most transformative sectors of the coming decade.

Tata Mutual Fund Temporarily Halts Fresh Subscriptions in Gold ETF and FoF Amid Surging Demand

Strong Inflows Highlight Safe-Haven Appeal, But Investors Must Review Overall Portfolio Allocation

Mumbai: Tata Mutual Fund has announced temporary restrictions on fresh subscriptions in its Gold Exchange Traded Fund (ETF) and Gold Fund of Fund (FoF). The move comes in response to exceptionally strong investor interest in gold-backed products amid global uncertainties and rising gold prices.

The restrictions mean that new investors or existing investors looking to make additional lump-sum investments in these schemes will not be able to subscribe until further notice. However, existing unitholders can continue to redeem or switch out of the schemes. Such temporary curbs are not uncommon when gold funds witness heavy inflows, as fund houses need time to efficiently deploy capital into physical gold or gold-related instruments without significantly impacting tracking error or liquidity.

This development underscores gold's growing importance in investor portfolios. While the temporary restriction may cause short-term inconvenience for those planning fresh investments, it also reflects strong underlying demand for the yellow metal. Long-term investors should view this as a reminder to maintain a disciplined allocation to gold typically 5-10% of the overall portfolio rather than chasing recent momentum.

Investors currently sitting on cash can explore Sovereign Gold Bonds (if available in the next tranche) or wait for the restrictions to be lifted. Those already holding gold ETFs or FoFs may consider reviewing their overall gold exposure to ensure it aligns with their risk profile and investment horizon. The move by Tata Mutual Fund is a signal that gold continues to attract attention as a defensive asset, but investors must avoid over-allocation driven purely by recent performance.

Hindustan Zinc Partners Sulfozyme Agro to Advance Sustainable Metal Recovery

Investment Opportunity in Green Mining: Partnership Strengthens ESG Credentials and Circular Economy Push

Udaipur: Hindustan Zinc has signed a partnership agreement with Sulfozyme Agro to develop sustainable technologies for metal recovery. The collaboration aims to use advanced bio-based solutions to recover valuable metals from mining waste, tailings, and low-grade ores in an environmentally responsible manner.

The initiative focuses on improving metal recovery rates while minimizing environmental impact. By adopting microbial and bioleaching processes, Hindustan Zinc aims to reduce waste generation, lower its carbon footprint, and move towards a circular economy model in mining operations. This aligns with the company's broader sustainability goals and regulatory expectations for responsible mining.

The partnership is a positive development for Hindustan Zinc. It strengthens the company's ESG credentials, which are increasingly important for institutional investors.

Improved metal recovery from waste can also enhance operational efficiency and generate incremental revenue over time.

Long-term investors can view this as part of Hindustan Zinc's ongoing efforts to modernize operations and adopt cleaner technologies. While near-term financial impact may be gradual, such initiatives improve the company's positioning in a sector where sustainability is becoming a key differentiator.

Adani Energy Acquires IntelliSmart for ₹3,050 Crore: Strategic Push into Smart Metering

Investment Opportunity in Smart Infrastructure: Acquisition Strengthens Adani's Position in Digital Energy Solutions and Power Distribution

Ahmedabad: Adani Energy has announced the acquisition of IntelliSmart, a leading smart metering and energy management solutions company, for ₹3,050 crore. The deal marks a significant step in Adani's strategy to expand its presence in the fast-growing smart infrastructure and digital energy space.

IntelliSmart specializes in Advanced Metering Infrastructure (AMI), IoT-based solutions, and data analytics for utilities. The acquisition will enable Adani Energy to integrate smart metering technology across its power distribution network, improve billing efficiency, reduce AT&C losses, and offer value-added services to consumers and discoms.

The move aligns with the government's ambitious target of installing over 250 million smart meters across India. It also positions Adani Energy to capture opportunities arising from the digital transformation of the power sector.

This acquisition is positive for Adani Energy and the broader Adani Group. It enhances technological capabilities in the energy distribution business and opens new revenue streams through smart solutions and data services.

While integration risks and execution timelines remain monitorable, the strategic fit with India's smart metering push and Adani's existing power ecosystem strengthens the long-term investment case. The deal reflects the group's focus on combining physical infrastructure with digital technology to create scalable business models.

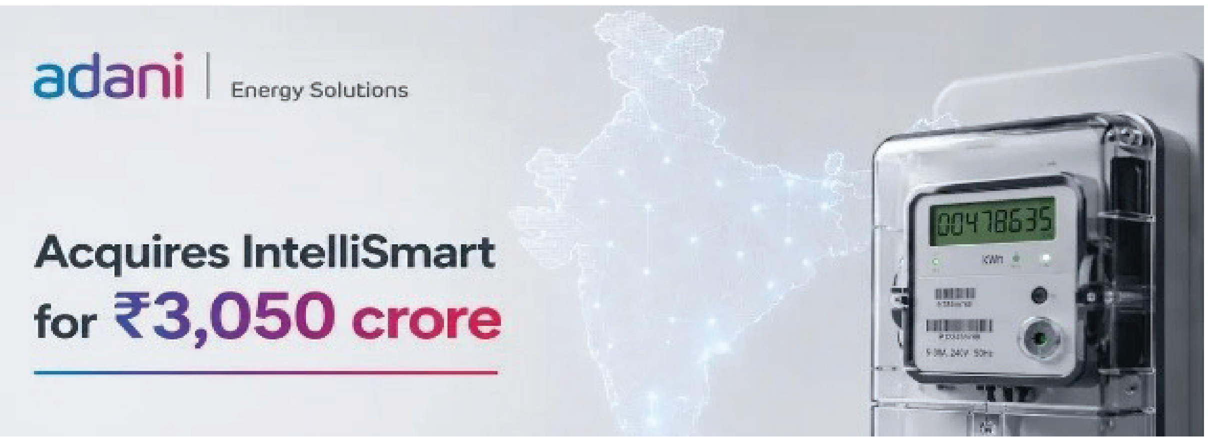

भारत का आउटवर्ड FDI मई में 49% गिरा: RBI डेटा ने दिखाई 4.49 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता

निवेशकों के लिए राहत या चिंता: विदेशी निवेश में कमी से रुपये को समर्थन, लेकिन वैश्विक विस्तार पर सतर्कता का संकेत

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के अनुसार, मई में भारत की आउटवर्ड FDI प्रतिबद्धताएं महीने-दर-महीने 49 प्रतिशत गिरकर 4.49 अरब डॉलर रह गईं। यह गिरावट वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनावों के बीच आई है।

आउटवर्ड FDI में यह कमी मुख्य रूप से भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में नए निवेश या अधिग्रहण में कमी को दर्शाती है। वैश्विक स्तर पर ऊंची ब्याज दरें, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कुछ क्षेत्रों में नियामकीय सख्ती ने भारतीय कंपनियों को विदेशी विस्तार में सतर्क कर दिया है।

हालांकि, लंबी अवधि में भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति मजबूत कर रही हैं। आईटी, फार्मा, मेटल्स और ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियां विदेशी अधिग्रहण के जरिए बाजार पहुंच और संसाधन हासिल करने का प्रयास करती रही हैं।

आउटवर्ड FDI में गिरावट निवेशकों के लिए मिश्रित संकेत देती है। एक ओर जहां यह वैश्विक जोखिमों के प्रति भारतीय कंपनियों की सतर्कता को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर इससे घरेलू स्तर पर पूंजी का पुनर्निवेश बढ़ सकता है।

निवेशक उन कंपनियों पर ध्यान दें जो मजबूत बैलेंस शीट और घरेलू विकास योजनाओं पर फोकस कर रही हैं। लंबी अवधि के निवेशक आउटवर्ड FDI के रुझान पर नजर रखें, क्योंकि यह भारतीय कॉर्पोरेट्स की वैश्विक महत्वाकांक्षा का संकेतक है।

लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इनकम में 19% की वृद्धि: अप्रैल-मई में मजबूत शुरुआत, सेक्टर में नई गति

इंश्योरेंस पेनेट्रेशन बढ़ने से लंबी अवधि की ग्रोथ संभावनाएं मजबूत, लिस्टेड कंपनियों को फायदा

मुंबई: भारतीय जीवन बीमा कंपनियों की प्रीमियम आय में अप्रैल-मई में 19 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की स्वस्थ स्थिति और बढ़ती मांग को दर्शाती है। नया बिजनेस प्रीमियम (NBP) और कुल प्रीमियम इनकम दोनों में अच्छी बढ़ोतरी हुई है।

इस वृद्धि के पीछे कई कारण हैं। बढ़ती आर्थिक गतिविधियां, मध्यम वर्ग की बढ़ती आय, डिजिटल वितरण चैनलों का विस्तार और बीमा जागरूकता में सुधार प्रमुख हैं। प्रोटेक्शन प्लान्स, यूलिप और सेविंग्स प्रोडक्ट्स की मांग में तेजी आई है। खासकर व्यक्तिगत प्रीमियम सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखी गई है। कर लाभ और वित्तीय सुरक्षा की बढ़ती जरूरत ने भी लोगों को बीमा की ओर आकर्षित किया है।

यह आंकड़ा लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बहुत सकारात्मक है। भारत में बीमा पेनेट्रेशन अभी भी वैश्विक औसत से काफी कम है, जिससे लंबी अवधि में जबरदस्त ग्रोथ की गुंजाइश बनी हुई है। लिस्टेड कंपनियां जैसे एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और एलआईसी को इस वृद्धि से फायदा होने की उम्मीद है।

निवेशक उन कंपनियों पर ध्यान दे सकते हैं जो प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स, डिजिटल क्षमता और वितरण नेटवर्क में मजबूत हैं। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस (VNB) मार्जिन और पर्सिस्टेंसी रेशियो पर नजर रखना जरूरी है। हालांकि प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और नियामकीय बदलाव भी आ सकते हैं, लेकिन समग्र सेक्टर आउटलुक सकारात्मक बना हुआ है। लंबी अवधि के निवेशक इंश्योरेंस थीम को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। यह वृद्धि दर्शाती है कि भारतीय परिवार अब वित्तीय सुरक्षा को गंभीरता से ले रहे हैं और बीमा क्षेत्र भविष्य में स्थिर और आकर्षक रिटर्न दे सकता है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने लॉन्च किया निफ्टी स्मॉलकैप 250 ETF: स्मॉलकैप सेक्टर में आसान और किफायती निवेश का नया विकल्प

हाई ग्रोथ स्मॉलकैप कंपनियों में डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर, लंबी अवधि के मजबूत रिटर्न की संभावना

चंडीगढ़: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्युचुअल फंड ने निफ्टी स्मॉलकैप 250 ETF लॉन्च किया है। यह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड निफ्टी स्मॉलकैप 250 इंडेक्स को ट्रैक करेगा, जिसमें भारत की टॉप 250 स्मॉलकैप कंपनियां शामिल हैं। नया फंड ऑफर (NFO) निवेशकों को स्मॉलकैप सेक्टर में आसान और किफायती निवेश का मौका दे रहा है। स्मॉलकैप कंपनियां आमतौर पर उच्च विकास क्षमता वाली होती हैं और आर्थिक विस्तार के साथ तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। यह ETF उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो सक्रिय फंड्स की तुलना में कम खर्च में डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर चाहते हैं।

यह ETF कम एक्सपेंस रेशियो, उच्च तरलता और पूर्ण पारदर्शिता प्रदान करता है। निवेशक स्टॉक एक्सचेंज पर किसी भी समय यूनिट्स खरीद या बेच सकते हैं। निफ्टी स्मॉलकैप 250 इंडेक्स में विभिन्न सेक्टर्स की कंपनियां शामिल हैं, जिससे एक ही फंड के जरिए व्यापक डाइवर्सिफिकेशन मिलता है।

स्मॉलकैप सेक्टर लंबी अवधि में उच्च रिटर्न की संभावना रखता है, लेकिन इसमें उतार-चढ़ाव भी ज्यादा होता है। यह ETF उन निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प है जिनका निवेश क्षितिज कम से कम 5-7 वर्ष का है और जो उच्च जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं।

निफ्टी स्मॉलकैप 250 ETF स्मॉलकैप थीम पर निवेश करने का सरल और प्रभावी तरीका है। सक्रिय स्मॉलकैप फंड्स की तुलना में इसमें खर्च कम है और स्टॉक चयन का जोखिम नहीं है। लंबी अवधि के निवेशक अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का 10-15% हिस्सा स्मॉलकैप एक्सपोजर में रख सकते हैं।

हालांकि स्मॉलकैप सेक्टर में मार्केट में गिरावट के दौरान ज्यादा उतार-चढ़ाव देखा जाता है, इसलिए निवेश से पहले अपनी जोखिम क्षमता का आकलन जरूर करें। NFO के दौरान या लिस्टिंग के बाद डीमैट अकाउंट के जरिए आसानी से निवेश किया जा सकता है।

यह ETF भारत की आर्थिक विकास कहानी से जुड़ने का एक अच्छा माध्यम है। निवेशक फंड के परफॉर्मेंस, ट्रैकिंग एरर और AUM ग्रोथ पर नजर रखें। स्मॉलकैप थीम लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दे सकती है, बशर्ते निवेश धैर्य के साथ किया जाए।

IN-SPACe Selects Astrobase, SatSure and TM2SPACE for First Technology Adoption Fund Grants

Government Backing to Accelerate Innovation and Strengthen India's Position in the Global Space Economy

Gurugram: startups Astrobase, SatSure and TM2SPACE for the first round of funding under its Technology Adoption Fund. This marks an important step in supporting indigenous innovation and strengthening India's private space ecosystem.

The selected startups are working on advanced solutions in satellite technology, data analytics and space systems. SatSure focuses on satellite-based data analytics for agriculture, insurance and infrastructure monitoring. Astrobase and TM2SPACE are developing critical technologies in satellite platforms and space infrastructure. The funding will help these companies scale their technologies and move towards commercial deployment.

IN-SPACe's initiative aims to bridge the gap between research and market-ready solutions, reducing reliance on imports and boosting India's capabilities in the global space economy.

This development is positive for the emerging space tech theme in India. It signals growing government support for private players in satellite services, data analytics and space systems. Investors can track companies with exposure to satellite technology, geospatial analytics and defence-space applications for long-term opportunities.While the sector remains early-stage and capital-intensive, consistent policy support and successful technology adoption could create meaningful value over the next 5–7 years. Investors should monitor execution by these startups and future funding rounds under the scheme.

सैटश्योर ने जुटाए 2.6 मिलियन डॉलर का ग्रांट: AI पावर्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन मॉडल विकसित करेगी

स्पेस टेक और AI आधारित जियोस्पेशियल एनालिटिक्स सेक्टर में नई ग्रोथ संभावनाएं

बेंगलुरु: स्पेस टेक स्टार्टअप सैटश्योर ने AI पावर्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन मॉडल विकसित करने के लिए 2.6 मिलियन डॉलर का ग्रांट हासिल किया है। यह फंडिंग कंपनी को सैटेलाइट डेटा का उपयोग कर उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाने में मदद करेगी।

सैटश्योर मुख्य रूप से सैटेलाइट इमेजरी और जियोस्पेशियल डेटा का विश्लेषण कर कृषि, बीमा, इंफ्रास्ट्रक्चर और जलवायु संबंधी समाधान प्रदान करती है। नए AI मॉडल से फसल निगरानी, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और शहरी नियोजन जैसी सेवाओं की सटीकता और गति बढ़ेगी। यह भारत की स्मार्ट एग्रीकल्चर और जलवायु लचीलापन लक्ष्यों को भी मजबूत करेगा।

यह ग्रांट स्पेस टेक और AI आधारित जियोस्पेशियल सेक्टर के लिए सकारात्मक संकेत है। भारत में सैटेलाइट डेटा की मांग तेजी से बढ़ रही है, खासकर कृषि, बीमा और सरकारी योजनाओं में। सैटश्योर जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।लंबी अवधि के निवेशक AI, स्पेस टेक और क्लाइमेट टेक थीम पर ध्यान दे सकते हैं। हालांकि यह सेक्टर अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन सरकारी समर्थन और बढ़ती मांग से भविष्य में अच्छी संभावनाएं हैं। निवेशक ऐसी कंपनियों की प्रगति, प्रोडक्ट कमर्शियलाइजेशन और आगे की फंडिंग पर नजर रखें।

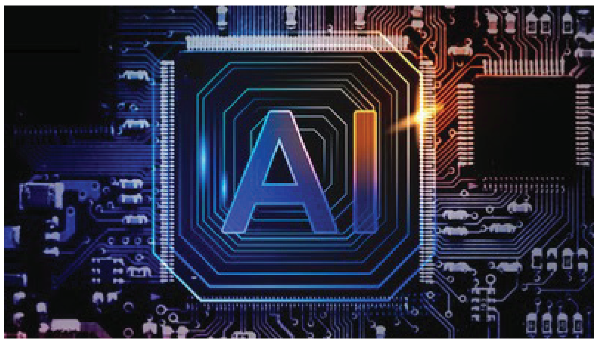

कोरम AI ने जुटाए 35 मिलियन डॉलर: फिजिकल सिक्योरिटी में AI की नई क्रांति

AI आधारित सुरक्षा समाधान सेक्टर में तेज ग्रोथ, स्मार्ट सिटी और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मिलेगा फायदा

मुंबई: सिक्योरिटी स्टार्टअप कोरम AI ने 35 मिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई है। यह राउंड Ansa Capital और Battery Ventures के नेतृत्व में पूरा हुआ है। कंपनी AI आधारित उन्नत सुरक्षा समाधान प्रदान करती है, जिसमें वीडियो एनालिटिक्स, रियल-टाइम थ्रेट डिटेक्शन और स्मार्ट सर्विलान्स सिस्टम शामिल हैं।

कोरम AI का प्लेटफॉर्म कैमरों और सेंसर से मिलने वाले डेटा का विश्लेषण कर सुरक्षा खतरों की पहचान करता है। यह पारंपरिक सुरक्षा प्रणालियों की तुलना में अधिक तेज और सटीक है। बढ़ते शहरीकरण, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और सुरक्षा चिंताओं के बीच ऐसे समाधानों की मांग तेजी से बढ़ रही है।

यह फंडिंग AI और फिजिकल सिक्योरिटी सेक्टर के लिए सकारात्मक संकेत है। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन, एयरपोर्ट, मेट्रो, इंडस्ट्रियल एरिया और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उन्नत सुरक्षा समाधानों की जरूरत बढ़ रही है। लंबी अवधि के निवेशक AI, साइबर सिक्योरिटी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पर ध्यान दे सकते हैं।

कोरम AI जैसी कंपनियों की सफलता से इस सेक्टर में और निवेश आने की संभावना है। निवेशक फंडिंग राउंड की प्रगति, प्रोडक्ट एडॉप्शन और वैश्विक विस्तार पर नजर रखें। यह विकास भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी मजबूत करेगा।

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj
Technical Head
anil.stockcare@gmail.com

All level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

• As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
• If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1
• If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
• Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
• If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
• If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock Name	closing	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	23623	24395	24020	23821	23446	23247	22872	22673
BANK NIFTY	56815	60861	58863	57839	55841	54817	52819	51795
SENSEX	75528	78535	77050	76289	74804	74043	72558	71797
FINNIFTY	25943	27585	26773	26358	25546	25131	24319	23904
MIDCAP	14246	14760	14509	14378	14127	13996	13745	13614
ACC	1344	1407	1375	1360	1328	1313	1281	1266
AXISBANK	1353	1483	1420	1387	1324	1291	1228	1195
ABCAPITAL	357	390	374	366	350	342	326	318
BHARTIARTL	1825	1920	1878	1852	1810	1784	1742	1716
BHEL	378	423	410	394	381	365	352	336
BIOCON	417	440	431	424	415	408	399	392
BEL	408	435	426	417	408	399	390	381
CDSL	1228	1291	1261	1244	1214	1197	1167	1150
DATAPATTERN	4522	5450	5086	4804	4440	4158	3794	3512
ESCORTS	2756	2947	2889	2823	2765	2699	2641	2575
EICHERMOTOR	7300	7849	7601	7451	7203	7053	6805	6655
FEDERALBANK	315	339	328	322	311	305	294	288
GRINFRAPOJECT	862	947	917	890	860	833	803	776
HDFCBANK	772	829	801	787	759	745	717	703
HCLTECH	1110	1220	1189	1150	1119	1080	1049	1010
HINDUNILVR	2163	2328	2266	2215	2153	2102	2040	1989
HAL	4194	4466	4393	4294	4221	4122	4049	3950
HYUNDAI	1991	2173	2086	2038	1951	1903	1816	1768
IOC	141	150	146	143	139	136	132	129
ICICIBANK	1340	1476	1410	1375	1309	1274	1208	1173
INFY	1119	1269	1235	1177	1143	1085	1051	993
ITC	286	298	292	289	283	280	274	271
KOTAKBNK	404	445	425	414	394	383	363	352
LICHOUSING	559	597	579	569	551	541	523	513
LT	4050	4328	4194	4122	3988	3916	3782	3710
LUPIN	2290	2379	2338	2314	2273	2249	2208	2184
MARUTI	13350	14140	13779	13564	13203	12988	12627	12412
M&M	3037	3241	3146	3091	2996	2941	2846	2791
MGL	1094	1177	1141	1117	1081	1057	1021	997
MAZGAONDOC	2413	2605	2528	2470	2393	2335	2258	2200
PFC	421	466	454	437	425	408	396	379
RECLTD	347	375	365	356	346	337	327	318
RELIANCE	1295	1361	1331	1313	1283	1265	1235	1217
SBIN	1016	1089	1054	1035	1000	981	946	927
SUNPHARMA	1807	1873	1844	1825	1796	1777	1748	1729
SHRIRAMFINANCE	957	1064	1012	984	932	904	852	824
TITAN	4179	4565	4402	4290	4127	4015	3852	3740
TCS	2161	2262	2222	2191	2151	2120	2080	2049
TATAMOTORS	391	423	409	400	386	377	363	354
UPL	611	678	657	634	613	590	569	546
VALIENT	279	309	298	288	277	267	256	246
WIPRO	180	209	201	191	183	173	165	155

राष्ट्रपति ने REC और PFC के विलय को मंजूरी दी: पावर फाइनेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव

विलय से लागत बचत, मजबूत बैलेंस शीट और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को मिलेगा नया बल

नई दिल्ली: राष्ट्रपति ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (REC) के पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) में विलय को मंजूरी दे दी है। यह कदम पावर फाइनेंस सेक्टर में बड़े पैमाने पर समेकन लाएगा और दोनों संस्थाओं की क्षमताओं को मिलाकर एक मजबूत इकाई बनाएगा।

विलय के बाद PFC जीवित इकाई के रूप में काम करेगा। इससे प्रशासनिक खर्चों में कमी आएगी, फंड जुटाने की क्षमता बढ़ेगी और जोखिम प्रबंधन बेहतर होगा। दोनों कंपनियां पहले से ही पावर सेक्टर को फंडिंग मुहैया कराती हैं। अब एकीकृत इकाई देश की बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से वित्त पोषित कर सकेगी।

यह विलय PFC और REC दोनों के शेयरधारकों के लिए सकारात्मक माना जा रहा है। लागत बचत, परिचालन दक्षता और बड़े पैमाने के फायदे से लंबी अवधि में मूल्य सृजन होने की उम्मीद है। शेयर बाजार में PFC के शेयरों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जा सकती है।

निवेशक स्वैप रेशियो, विलय की समयसीमा और एकीकरण की प्रगति पर नजर रखें। पावर सेक्टर में सरकारी फोकस और बढ़ते पूंजीगत व्यय को देखते हुए यह विलय सेक्टर को और मजबूत करेगा। लंबी अवधि के निवेशक पावर फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग थीम पर ध्यान दे सकते हैं। हालांकि एकीकरण के दौरान कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन समग्र दृष्टिकोण सकारात्मक है।

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.

प्रकाशक एवं मुद्रक: प्रदीप कारबेलकर, सी-101, नेहरू नगर स्वत्वाधिकार द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रा.लि., इ-4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462016, से प्रकाशित एवं DigitalLok, सागर हाई स्ट्रीट, अयोध्या बायपास रोड, डी मार्ट के पास, भोपाल, (म.प्र.) - 462010। संपादक: प्रदीप कारबेलकर (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)। फोन: +9198262 23075 वेबसाइट: www.investmentavenues.in